

न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)
अपील एल०आर०ए० संख्या 277/2020 जिला टोंक।

मुंशी शाह पुत्र कासम शाह, जाति साईं, निवासी बस्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक।
—अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निवाई जिला टोंक।

—असल रेस्पोंडेंट

2. जैतून पुत्री कासम शाह

3. खातून पुत्री कासम शाह

4. चन्दा पुत्री कासम शाह

5. रईसा पुत्री कासम शाह

जाति साईं, निवासी बस्सी, तहसील निवाई, जिला टोंक।

—प्रफोर्मा रेस्पोंडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय विद्वान जिला कलक्टर महोदय, टोंक दिनांक 29.12.1999 जो प्रकरण संख्या 19/1993 बउनवानी सरकार बनाम कासम खां में पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषक:— श्री गिरीश शर्मा(वकील अपी०)

श्री आकाश पारीक—(राजकीय अभि०)

निर्णय

दिनांक:—15.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम बस्सी तहसील निवाई जिला टोंक के आराजी खसरा नम्बर 140 में से 2 बीघा भूमि अपीलांत एवं रेस्पोंडेंट संख्या 2 से 5 के पिता कासम पुत्र जुम्मा जाति साईं मुसलमान के पक्ष में आवंटन सलाहकार समिति टोंक द्वारा दिनांक 26.10.1977 को नियमन की गई। नियमन के पश्चात उक्त भूमि पर अपीलांत के पिता एवं उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलांत और रेस्पोंडेंट संख्या 2 लगायत 5 काबिजकाश्त चले आ रहे हैं। आवंटन के पश्चात उक्त भूमि गैर खातेदारी के रूप में अपीलांत के पिता कासम के नाम दर्ज की गई थी। तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 29.03.1993 को कासम पुत्र जुम्मा के पक्ष में किये गये उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु जिला कलक्टर टोंक के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) में भूमि आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया। कार्यवाही के दौरान कासम की मृत्यु हो गई। वारिसान को जवाब का अवसर दिये बिना जिला कलक्टर टोंक द्वारा दिनांक 29.12.1999 को कासम पुत्र जुम्मा के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 को निरस्त कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर उक्त अपील निम्न आधार पर प्रस्तुत की जा रही है—

1. कासम खान की मृत्यु के बाद उसके वारिसान को कायम मुकाम नहीं लिया जाकर पत्रावली पर निर्णय किया गया जो उचित नहीं है।

2. खसरा नम्बर 140 का पूर्ण रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा था। जिसमें से 18 बिघा भूमि दिनांक 19.03.1976 को जरिये नामांतरण संख्या 440 वन विभाग के नाम लग चुकी थी। शेष भूमि 13 बिघा 1 बिस्वा रही, जिसमें से 2 बीघा हमे मिली है और बिना हमे सुने प्रकरण का निर्णय जिला कलक्टर द्वारा किया गया जो गलत है। अतः जिला कलक्टर टोंक द्वारा पारित निर्णय

दिनांक 29.12.1999 को निरस्त किया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 को बहाल किया जायें। अपील के साथ अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना मय शपथ पत्र धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम मय शपथ पत्र एक अन्य प्रार्थना पत्र नियम 17 , 32 रेवन्यु कोर्ट मैनुअल पार्ट 2 मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

अपील के साथ प्रकरण संख्या 19/1993 तहसीलदार निवाई बनाम कासम केस की ऑर्डरशीट प्रार्थना पत्र 14(4), जिला कलक्टर का निर्णय दिनांक 29.12.1999 प्रस्तुत किये।

अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को नोटिस जारी कर रिकोर्ड मंगवाया जाने का आदेश जारी किया गया। रिकोर्ड प्राप्त किया गया।

सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अवधि अधिनियम प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार अभी हाल ही में उसके द्वारा ऋण संबंधित कार्यवाही करने हेतु जमाबंदी ली। उसे ज्ञात हुआ कि भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई है। दिनांक 13.12.2019 को अभिभाषक से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि अपील का निर्णय दिनांक 29.12.1999 को हो चुका है। निर्णय की प्रति प्राप्त करने हेतु उसी दिन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 26.12.2019 को नकल प्राप्त कर अपील की कार्यवाही हेतु दिनांक 16.01.2020 को अजमेर आकर नकल प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई। देरी को क्षमा किया जाये। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है कि दिनांक 13.12.2019 को 1205 क्रमांक से उसके द्वारा नकल हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था जो दिनांक 26.12.2019 को उसे प्राप्त हुई है। न्यायालय हाजा में अपीलांट द्वारा दिनांक 20.01.2020 को अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। जानकारी दिनांक से अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 17, 32 रेवन्यु कोर्ट मैनुअल पार्ट-2 का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.12.1999 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है। जो अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने से छूट प्रदान की जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। जो नकल उसे अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रमाणित प्रति प्रस्तुतीकरण से उसे छूट प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय की आड़ में रेस्पोजेंट उसे जबरन बेदखल करने एवं अन्यत्र आवंटन करने हेतु आमदा है। जिसकी वजह से अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। मौके व राजस्व रिकोर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाये एवं अन्य के पक्ष में आवंटन/नियमन नहीं किया जाये। विवादित भूमि चूंकि सिवायचक है। प्रार्थी स्वयं कहता है कि अन्य के पक्ष में आवंटन/नियमन नहीं किया जाये। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं बनता है। प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

बहस उभयपक्ष अभि0 सुनी गई, बहस के दौरान वकील अपीलांट के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 140 का कुल रकबा 31 बिघा 1 बिस्वा था जिसमे से 18 बिघा भूमि वनविभाग के नाम दर्ज की गई। शेष खसरा नम्बर 140 की 13 बिघा 1 बिस्वा भूमि सिवायचक बनी रही जिसमें से अपीलांट को भूमि आवंटन किया गया है। संवत् 2049 में अपीलांट के पिता को खातेदारी मिल गई थी। जबकि धारा 14(4) की कार्यवाही दिनांक 29.03.1993 को की गई। अपीलांट के पिता की खातेदारी 1983 में ही हो चुकी है। धारा 14(4) का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। न्यायिक दृष्टांत 1988 आरआरडी पेज 689, 1987 आरआरडी 359 से स्पष्ट है।

जिला कलक्टर टोंक द्वारा कासम पुत्र जुम्मा के वारिसान को पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र अनिर्णित रखते हुए निर्णय किया गया जो कि न्यायिक दृष्टांत 2009 आरआरटी (2) उच्च न्यायालय पेज 930 व 2009(1) पेज 139 के विपरित होकर निरस्त योग्य है। जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 29.12.1999 की पालना में भूमि सिवायचक दर्ज की गई है, ना कि वनविभाग के नाम। अतः अपील स्वीकार की जायें।

बहस के दौरान वकील अपीलांट द्वारा नामांतरण पंजिका ग्राम बस्सी का नामांतरण संख्या 440 व 1161 की प्रमाणित प्रतिलिपीयां प्रस्तुत की तथा न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1987 पेज 359, आरआरडी 1988 पेज 689, आरआरटी 2009(2) पेज 931, आरआरटी 2009(1) पेज 139, आरआरटी 2002(1) पेज 649 प्रस्तुत किये।

राजकीय अभि० ने बहस के दौरान यह बताया कि जिला कलक्टर टोंक का आदेश विधिवत है। भूमि आवंटन से पूर्व वन विभाग के नाम दर्ज हो चुकी थी। अतः अपील खारिज की जायें।

जिला कलक्टर टोंक के निर्णय दिनांक 29.12.1999 का अवलोकन किया गया। उनके निर्णय के पैरा-4 के अनुसार खसरा नम्बर 140 की 18 बिघा भूमि राज्य आदेश दिनांक 18.08.1964 के अनुसार दिनांक 12.11.1964 को वन विभाग के नाम कर दी गई है। आवंटन सलाहकार द्वारा भूमि के आवंटन के नियमन की कार्यवाही की गई है। उस दिन भूमि आवंटन/नियमन के लिए उपलब्ध नहीं थी। वन विभाग के नाम उक्त भूमि दिनांक 19.03.1976 को स्वीकृत हो चुकी थी। अतः पश्चातवृत्ति भूमि आवंटन को उचित नहीं माना जा सकता है तथा अपीलांट के पक्ष में किया गया नामांतरण संख्या 482 दिनांक 12.06.1978 को खारिज योग्य माना गया।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत 14(4) के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उसके पैरा-2 के अनुसार ग्राम बस्सी में नामांतरण संख्या 440 दिनांक 19.03.1976 द्वारा उक्त खसरा नम्बर 140 की 18 बिघा भूमि वन विभाग के नाम दर्ज की गई थी, जिसका अमल जमाबंदी पर लाल स्याही से नोट लगाकर संवत् 2032-35 की जमाबंदी में कर दिया गया था। इस प्रकार उसी भूमि का पुनः अप्रार्थी कासम पुत्र जुम्मा जाति साईं के नाम नामांतरण दर्ज करने या आवंटन करने का कोई औचित्य नहीं था। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि आवंटन के लिए उपलब्ध नहीं थी। प्रार्थना पत्र के पैरा-6 में यह दर्ज किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 मण्डल वन अधिकारी टोंक को नॉर्मल पार्टी बनाया गया। प्रार्थी उससे कोई रिलिफ नहीं चाहता है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.1996 में प्रार्थी मुंशी पुत्र कासम है। जो प्रार्थना पत्र में बताता है कि दिनांक 25.10.1994 को उक्त प्रकरण में एकतरफा किया जाने का आदेश हो चुका है। प्रतिवादी को तामील नहीं हुई है मगर न्यायालय द्वारा तामील मानी जाकर एकतरफा कार्यवाही का आदेश दिया है। अतः एकतरफा कार्यवाही निरस्त कर सुनवाई का अवसर दिया जायें।

अपीलांट अभिभाषक द्वारा लिखित में अपनी ओर से छः बिन्दु बनाकर एक प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात प्रस्तुत किये। जिसमें क्रम संख्या 1 पर नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 जिसमें खसरा नम्बर 140 कुल रकबा 31 बीघा 1 बिस्वा में से राज्य सरकार के आदेश में से खसरा नम्बर 140 की 18 बीघा भूमि महकमा जंगलात के नाम की। शेष खसरा नम्बर 140 की 13 बीघा 1 बिस्वा सिवायचक में से प्रार्थी अपीलांट को आवंटन किया गया। क्रम संख्या 2 पर जमाबंदी संवत् 2049 में अपीलांट के पिता के खातेदारी में भूमि दर्ज की। जबकि 14(4) की कार्यवाही दिनांक 29.03.1993 को की गई। जबकि अपीलांट के पिता के विवादित भूमि 1983 में ही

खातेदारी में दर्ज थी। खातेदारी अधिकार मिलने के पश्चात धारा 14(4) का प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था। सन् 1988 आरआरडी पेज 689, 1987 आआरडी पेज 359 प्रदशः 2 से स्पष्ट है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु नम्बर 3 के अनुसार कलक्टर महोदय द्वारा सभी वारिसान जो कासम खान पुत्र जुम्मा के थे, उन्हें पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। उनके द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी अनिर्णित रख दिया। उनका निर्णय 2009 आरआरटी (2) एस0सी0पेज 931 व 2009(1) आरआरटी पेज 139 के विपरीत होकर काबिज निरस्त योग्य है। उनका निर्णय अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित किया गया है। प्रार्थना पत्र के बिन्दु नम्बर 4 के अनुसार धारा 5 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2002(1) आरआरटी पेज 648 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर अच्छा हों वहां मियाद के बिन्दु को गौण रखना चाहिए। उक्त प्रकरण में रसपो0 का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर टोंक के समक्ष संधारण योग्य नहीं था। क्योंकि प्रार्थना पत्र दिनांक 29.03.1993 को प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही प्रार्थी के पिता के उक्त खसरा नम्बर खातेदारी में दर्ज थे। प्रार्थना पत्र के बिन्दु नम्बर 5 के अनुसार रसपो0 द्वारा कलक्टर टोंक के समक्ष वन विभाग प्रार्थना पत्र में पक्षकार तो बनाया लेकिन उनको किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन निर्णय में भी उनको पक्षकार नहीं बनाया गया। क्योंकि राज्य सरकार के आदेश के अनुसार खसरा नम्बर 140 के 18 बीघा भूमि पूर्व में ही महकमा जंगलात के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई थी। प्रार्थना पत्र के बिन्दु नम्बर 6 के अनुसार कलक्टर टोंक के आदेश दिनांक 29.12.1999 की पालना में उपरोक्त भूमि सिवायचक दर्ज की गई है। जबकि उक्त आदेश की पालना में यदि उक्त भूमि वन विभाग की होती तो महकमा जंगलात के नाम से दर्ज की जानी चाहिए थी। जो कि सिवायचक है, प्रदशः 3 से स्पष्ट है। प्रदशः 1 नामांतरण संख्या 440 ग्राम बस्सी सत्यप्रतिलिपी है। प्रदशः 2 जमाबंदी संवत् 2049-52 ग्राम बस्सी खाता संख्या नया 14 प्रदशः 3 नामांतरण संख्या 1161 ग्राम बस्सी की फोटोप्रति है।

पत्रावली पर उपलब्ध ऑर्डरशीट प्रकरण संख्या 19/1993 तहसीलदार निवाई बनाम कासम का पुत्र जुम्मा अन्तर्गत धारा 14(4) का अवलोकन किया गया। प्रोसिडिंग दिनांक 28.06.1993 के अनुसार "पैरोकार हाजिर विपक्षी कासिम फौत हो चुका है। अतः तहसीलदार से कासम के वारिसान की सूची तलब की जायें। अन्य विपक्षी एवं मिसल की भी तलबी की जाकर दिनांक 20.09.1993 को पेश है। प्रोसिडिंग दिनांक 25.10.1994 के अनुसार पैरोकार हाजिर मृतक कासम के वारिसान की तलबी में उसके वारिस मुंशी की तलबी की गई। अप्रार्थी मुंशी बावजूद तामील नोटिस गैर हाजिर अतः उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। मिसल तलब कर दिनांक 20.12.1994 को पेश हो"

दिनांक 11.09.1996 को अप्रार्थी की ओर से एक वकालतनामा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु बाबूलाल सोनी अभिभाषक द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया है। दिनांक 11.08.1997 की प्रोसिडिंग के अनुसार मुंशीखां पुत्र कासम खां की ओर से श्री जितेन्द्र जैन एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया गया। मिशल प्राप्त नहीं हुई। इसके बाद पत्रावली मिशल के इंतजार में चलती रही। प्रोसिडिंग दिनांक 21.07.1999 के अनुसार पैरोकार एवं वकील विपक्षी उपस्थित है। पत्रावली प्राप्त हो गई है। वास्ते बहस दिनांक 04.08.1999 को पेश की। दिनांक 29.12.1999 को तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आवंटन निरस्त कर दिया।

वकील अपीलांट की इस बात में दम नहीं है कि बिना मिसल प्राप्त हुए आवंटन को निरस्त किया गया। दिनांक 21.07.1999 को पत्रावली प्राप्त हो चुकी थी। जो ऑर्डरशीट के अवलोकन से स्पष्ट है।

तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांतरण संख्या 440 दिनांक 19.03.1976 के द्वारा खसरा नम्बर 140 , 18 बीघा भूमि ग्राम बस्सी वन विभाग के नाम दर्ज की गई है। जबकि कासम पुत्र जुम्मा जाति साईं ग्राम बस्सी में खसरा नम्बर 140 में रकबा 2 बीघा आवंटन नामांतरण संख्या 489 दिनांक 12.06.1978 के द्वारा किया गया। उक्त आवंटन वन विभाग के आवंटन के पश्चात किया गया था। तहसीलदार ने इस वजह से यह माना है कि उसी भूमि(वन विभाग) का पुनः अन्य को आवंटन करने का कोई औचित्य नहीं है।

जहां तक बहस में अपीलांत अभिभाषक द्वारा यह बताया गया कि कासम खान की मृत्यु के बाद सिर्फ मुंशीखां को नोटिस दिये गये , बाकी को नहीं दिये गये तथा एल0आर0 का प्रार्थना पत्र पैडिंग रखा गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ऑर्डरशीट एवं पत्रावली पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। दिनांक 28.06.1993 से पत्रावली पर यह आ चुका था कि कासम खान की मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिस की सूची तलब किये जाने का निर्देश दिया गया। विपक्षी को तामील भेजी गई थी। दिनांक 25.10.1994 की प्रोसिडिंग के अनुसार बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर मुंशीशाह के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की आज्ञा दे दी थी। दिनांक 11.09.1996 को मुंशीशाह द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। इस पत्र में मुंशी ने यह बताया कि वह कासम पुत्र जुम्मा साईं का वारिस है और साथ में अपना शपथ पत्र भी दिया तथा एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने बाबत शपथ पत्र दिया गया। स्वयं उसके द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र में तथ्यों को छुपाया गया तथा प्रार्थना पत्र में यह नहीं बताया कि कोई अन्य भी पक्षकार है। अतः अपीलांत अभिभाषक द्वारा बहस में उठाया गया उक्त आक्षेप खारिज योग्य है। जमाबंदी सवंत 2049-52 के खाता संख्या 214 नया के अनुसार जमाबंदी के कॉलम नम्बर 4 में मुंशी पुत्र कासम जाति मुसलमान साईं शाकिन्दह दर्ज है। इनका स्टेटस क्या खातेदार अथवा गैर खातेदार है यह अंकित नहीं किया है। कॉलम नम्बर 5 में खसरा नम्बर 140 मीन , 140 मीन लिखा हुआ है तथा इसके सामने क्षेत्रफल 1 बीघा तथा 2 बीघा दर्ज है। नामांतरण संख्या 902 दिनांक 27.01.1994 से उन्पत की बजाय मुंशी पुत्र कासम के नाम अंकन स्वीकार करने का उल्लेख किया है। नामांतरण संख्या 1161 से मुंशी पुत्र कासम के नाम दर्ज 2 बीघा भूमि सिवायचक कर दी गई।

चूंकि अपीलांत द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है। अतः बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसके जिम्मे है। अपीलांत को आवंटन के समय जो भूमि आवंटित की गई थी। उस भूमि बाबत नक्शा ट्रेस कब्जा नो तोड़ एवं उसके बाद की गिरदावरी आदि प्रस्तुत करनी चाहिए थी। जो उसके द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये। अपीलांत यह कहकर आया है कि उसे दो बीघा भूमि वन विभाग को आवंटित भूमि के अलावा शेष रही भूमि में से मिली है। यह स्पष्ट नहीं करवाया है कि अपीलांत द्वारा सबूत, दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। जिला कलक्टर टोंक द्वारा मुख्य रूप से अपने निर्णय में यह मत लिया है कि विवादित भूमि वन विभाग के नाम दर्ज थी और कासम को आवंटन से पूर्व ही वन विभाग को आवंटन हो चुकी थी। अतः कासम को किया गया आवंटन बाद में किया गया है। जो किसी भी हालत में बहाल नहीं रखा जा सकता है। जिला कलक्टर टोंक के न्यायालय में अपीलाधीन प्रकरण में अपीलांत को सुनवाई का अवसर दिया गया था। अपील सुनवाई में वह उपस्थित हुआ था तथा उसकी ओर से अभिभाषक भी न्यायालय में उपस्थित हुए थे। अपील अपीलांत खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय प्रकरण संख्या 19/1993 अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 प्रार्थना पत्र विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 26.10.1977 निर्णय दिनांक 29.12.1999 द्वारा जिला कलक्टर टोंक यथावत रखा जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 15.06.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर